देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 18.03.2026
समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा– प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत नहीं; लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।
- प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए पन्द्रह दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- फायर सीजन के दौरान वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए सरकार, आजमन और संस्थाओं को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेगी।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह राशि साइबर अपराधों से निपटने, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने देहरादून में साइबर उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग–109 से जुड़े मार्ग के पुनर्निर्माण और शिमला–पिस्तौर–कुरैया मोटर मार्ग के सुधार कार्य भी किए जाएंगे।

इसके अलावा रुड़की में उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय के निर्माणाधीन भवन के लिए एप्रोच मार्ग बनाया जाएगा। मसूरी स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के भवन का अनुरक्षण किया जाएगा, वहीं खटीमा के राजकीय जनजाति छात्रावास में ट्यूबवेल और मास्ट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी।

एलपीजी

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

नैनीताल जिले के भ्रमण के दौरान उन्होंने बताया कि एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों में भी व्यावसायिक सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है।

इस बीच, सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को लेकर निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब हर दिन दो हजार छह सौ पचास सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और कंपनियों को आपूर्ति की जानकारी जिलाधिकारियों को देनी होगी। इसके लिये मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके अनुसार देहरादून को 31 प्रतिशत, हरिद्वार व नैनीताल को 13–13 प्रतिशत और, बाकी जिलों को जरूरत और कनेक्शन संख्या के अनुसार सिलेंडर मिलेंगे।

जखीरा बरामद

उत्तराखंड पुलिस ने उधमसिंह नगर जिले में लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की नकली एनसीईआरटी पुस्तकों का बड़ा जखीरा बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार 14 मार्च की रात रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आनंदम रिजॉर्ट के पास एक कैंटर वाहन को रोककर जांच की। चालक द्वारा पुस्तकों को मेरठ से लाने की जानकारी दी गई, लेकिन ई–वे बिल न होने और बिलों में भिन्नता मिलने पर संदेह हुआ। इसके बाद तलाशी में बड़ी मात्रा में पुस्तकें बरामद की गईं। जांच के दौरान बताए गए गोदाम की तलाशी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली गई, जहां भारी मात्रा में पुस्तकों का भंडारण मिला। एनसीईआरटी की टीम द्वारा जांच में इन पुस्तकों को नकली पाया गया। पुस्तकों की छपाई, कागज, बाइंडिंग और कवर डिजाइन मानकों के अनुरूप नहीं थे और लोगो में भी बदलाव कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया था।

मामले में रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इस कार्रवाई पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए पुरस्कार देने की घोषणा की है।

समीक्षा

राज्य में अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण–एस.आई.आर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में कम मैपिंग वाले ज़िलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सतासी प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में प्रगति कम है, जिसे तेजी से पूरा करने को कहा गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों में बीएलओ के साथ नगर निगम कर्मियों की भी तैनाती करने और उनकी नियमित ट्रेनिंग जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही एसआईआर से पहले सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने को कहा गया।

विशेष अभियान

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए पन्द्रह दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके तहत सैम्पलिंग के साथ जनजागरूकता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए मुख्य पड़ावों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और स्थानीय व्यापार संघों के साथ मिलकर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित होर्डिंग लगाने, व्यापारियों को आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने और मोबाइल वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच कराने के निर्देश भी दिए।

डॉ. रावत ने प्रदेशभर में साप्ताहिक बाजारों, हाट और मेलों में विशेष निरीक्षण करने को कहा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

वनाग्नि नियंत्रण

उत्तराखंड सरकार ने फायर सीजन के दौरान वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए इस बार आजमन और संस्थाओं को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और जंगलों में आग की घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है।

श्री उनियाल ने बताया कि विभाग की तैयारियां पूरी हैं और इस बार व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को आपदा की श्रेणी में रखा गया है और हर ज़िले में पीसीएस स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है। साथ ही फायर वाचकों का सामूहिक बीमा भी कराया गया है, ताकि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जा सके।

मॉक ड्रिल

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल के पहले चरण में कल बागेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में व्यापक स्तर पर बहु–स्थलीय अभ्यास किए गए। इन मॉक ड्रिल के माध्यम से संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, विभागों के बीच समन्वय और राहत–बचाव तंत्र की तैयारियों को परखा गया।

मॉकड्रिल के दौरान भूकम्प, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना, नदी में बाढ़, वनाग्नि और अन्य आपात स्थितियों के विभिन्न परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया। इसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, स्वास्थ्य, विद्युत और राजस्व विभाग सहित अन्य एजेंसियों ने मिलकर रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार और राहत कार्यों का

अभ्यास किया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से सभी ज़िलों में चल रहे अभ्यासों की लगातार निगरानी की गई।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि ऐसे अभ्यास आपदा के समय गोल्डन ऑवर में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इन अभ्यासों से मिली सीख के आधार पर कमियों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर किया जा सकता है, जिससे जन–धन की हानि को कम किया जा सके।

इस राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के दौरान प्रशासनिक तैयारियों का परीक्षण करना, विभागों के बीच समन्वय को मजबूत बनाना और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और बेहतर करना है, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की देरी या भ्रम की स्थिति न बने।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा– प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत नहीं; लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।
- प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए पन्द्रह दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- फायर सीजन के दौरान वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए सरकार, आजमन और संस्थाओं को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेगी।